

## भारत में ई-अपशष्टि प्रबंधन

### प्रलमिस के लयि:

ई-अपशष्टि (प्रबंधन) नयिम 2022, भूजल संदूषण, वायु परदूषण, मृदा कषरण, वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव (EPR), खतरनाक अपशष्टि के सीमा पार आवागमन और उनके नपिटान के नयितरण पर बेसल कनर्वेशन, परससिटेंट कार्बनकि परदूषकों पर स्टॉकहोम कनर्वेशन, खतरनाक और अन्य अपशष्टि (प्रबंधन एवं सीमा पार आवागमन) नयिम 2016, लैंडफलिगि ।

### मेन्स के लयि:

ई-अपशष्टि प्रबंधन से संबंधति नीतगित पहल एवं कार्यक्रम, भारत में ई-अपशष्टि का वर्तमान परदृश्य, ई-अपशष्टि प्रबंधन से संबंधति चुनौतियौ और इसके सामाजकि-आर्थकि नहितारिथ ।

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

### चर्चा में क्यौ?

हाल ही में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री द्वारा उपलब्ध आँकड़ों से देश भर में इलेक्ट्रॉनिक तथा वदियुत उपकरणों के बढ़ते उपयोग पर प्रकाश पड़ा है ।

### ई-अपशष्टि

- [इलेक्ट्रॉनकि अपशष्टि \(ई-अपशष्टि\)](#) से तात्पर्य ऐसे वदियुत एवं इलेक्ट्रॉनकि उपकरणों से है जो पुराने हो गए हैं या जो कार्यशील नहीं हैं ।
- ई-अपशष्टि में अनेक वषिले रसायन होते हैं जनिमें सीसा, कैडमियम, पारा तथा नकिल जैसी धातुएँ शामिल हैं ।

### भारत में ई-अपशष्टि की स्थति क्यौ है?

- मात्रा में वृद्धि: भारत में पछिले पाँच वर्षों में ई-अपशष्टि के उत्पादन में 72.54% की वृद्धि ( जो वर्ष 2019-20 के 1.01 मिलियन मीटरकि टन (MT) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1.751 मिलियन मीटरकि टन हो गया है) देखी गई है ।
  - प्रतविरष लगभग 57% ई-अपशष्टि (990,000 मीटरकि टन के बराबर) अनुपचारति रह जाता है ।
  - भारत के 65 शहरों से कुल ई-अपशष्टि का 60% से अधिक उत्पादति होता है जबकि 10 राज्यों की कुल ई-अपशष्टि में 70% भागीदारी है ।
- पुनर्रचकरण अंतराल: वर्ष 2023-24 में केवल 43% ई-अपशष्टि का पुनर्रचकरण (वर्ष 2019-20 में यह 22% था) कयिा गया ।
  - ई-अपशष्टि के प्रबंधन में अनौपचारकि कषेत्रों का वर्चस्व है तथा इनमें पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अभाव है ।
- वैश्वकि संदर्भ: चीन एवं अमेरिका के बाद भारत वशि्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ई-अपशष्टि उत्पादक देश है ।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में वशि्व भर में लगभग 53.6 मीटरकि टन ई-अपशष्टि उत्पन्न हुआ ।

### ई-अपशष्टि (प्रबंधन) नयिम

- ई-अपशष्टि (प्रबंधन) नयिम 2022:
  - वसितारति उत्पादक उत्तरदायतिव (EPR): उत्पादकों को पंजीकृत पुनर्रचकरणकर्त्ताओं के माध्यम से वार्षकि पुनर्रचकरण लक्ष्य प्राप्त करना अनविर्य है ।
    - EPR प्रमाण-पत्र से पुनर्रचकरति उत्पादों हेतु जवाबदेही सुनश्चिति होती है ।
  - वसितारति उत्पाद कवरेज: वतिव वर्ष 2023-24 से इसके तहत 106 वदियुत एवं इलेक्ट्रॉनकि उपकरणों (EEE) को शामिल कयिा गया ।
  - थोक उपभोक्ताओं का एकीकरण: सार्वजनकि संस्थानों एवं कार्यालयों द्वारा पंजीकृत पुनर्रचकरणकर्त्ताओं/नवीनीकरणकर्त्ताओं के माध्यम से ई-अपशष्टि का नपिटान कराने पर ज़ोर दयिा गया ।

- पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्त्ताओं और नवीनीकरणकर्त्ताओं को ई-अपशिष्ट के संग्रहण एवं प्रसंस्करण के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया।
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) द्वितीय संशोधन नियम, 2023: ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के नियम 5 के अंतर्गत, प्रशीतन एवं वातानुकूलन वनिर्माण में सुरक्षति, जवाबदेह तथा धारणीय रेफ्रिजिरेट प्रबंधन सुनिश्चिती करने के क्रम में खंड 4 जोड़ा गया।
- ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2024:
- केंद्र सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, उसके अनुमोदन से वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के व्यापार हेतु प्लेटफॉर्म स्थापति कर सकती है।
  - केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वसितारति उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण-पत्रों के लिये मूल्य सीमा निर्धारण किया जाएगा जो गैर-अनुपालन के क्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का 100% (अधिकतम) एवं 30% (न्यूनतम) होगा।

## ई-अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन/अभिसमय कौन-से हैं?

- अंतरराष्ट्रीय:
  - खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों एवं उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन (1989)।
    - भारत बेसल कन्वेंशन का एक पक्षकार है।
  - बामाको कन्वेंशन (1991): इसके तहत अफ्रीका में खतरनाक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट सहित) के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है तथा इस महाद्वीप से ऐसे अपशिष्ट की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित किया गया है।
  - पारा पर मनिमाता कन्वेंशन (2013)
    - भारत ने वर्ष 2018 में मनिमाता कन्वेंशन की पुष्टि की।
  - स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POP) (2001)
    - भारत ने स्टॉकहोम कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है तथा घरेलू कानूनों के माध्यम से इसके प्रावधानों को क्रियान्वित करने पर जोर दिया है।
- राष्ट्रीय:
  - ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022: इसके तहत EPR और उचित पुनर्चक्रण पर जोर दिया गया है।
- हानिकारक अपशिष्ट (प्रबंधन और पारगमन गतिविधि) नियम, 2016
  - रासायनिक एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय कार्ययोजना: स्टॉकहोम और रॉटरडैम सम्मेलनों के प्रति प्रतिबद्धताओं को प्रतिबिंबित किया गया है।

## भारत में ई-अपशिष्ट निपटान के सामान्य तरीके क्या हैं?

- लैंडफिलिंग: इसके तहत ई-अपशिष्ट को मृदा के अंदर डंप करना शामिल है।
  - एक गंभीर चिंता का विषय यह है कि संकटजनक पदार्थों का मृदा और भूजल में रसिकर पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने का खतरा है।
- भस्मीकरण (Incineration): उच्च तापमान (900-10,000 डिग्री सेल्सियस) पर ई-अपशिष्ट का नियंत्रित विधिसे दहन करने से अपशिष्ट की मात्रा कम हो जाती है और कुछ संकटजनक पदार्थ नष्टिप्रभावी हो जाते हैं।
- पुनर्चक्रण: मूल्यवान सामग्री (जैसे- धातु, प्लास्टिक) को पुनः प्राप्त करने के लिये ई-अपशिष्ट को नष्ट करना और वशिकृत घटकों का सुरक्षित रूप से वनिष्टीकरण करना। यह पारा, कैडमियम और सीसा जैसे संकटजनक पदार्थों को कम करता है, जिससे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य जोखिम कम होते हैं।
  - उदाहरण: मुद्रति सर्कटि बोर्ड, सी.आर.टी., मोबाइल फोन और तारों का पुनर्चक्रण।

## ई-अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे और संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

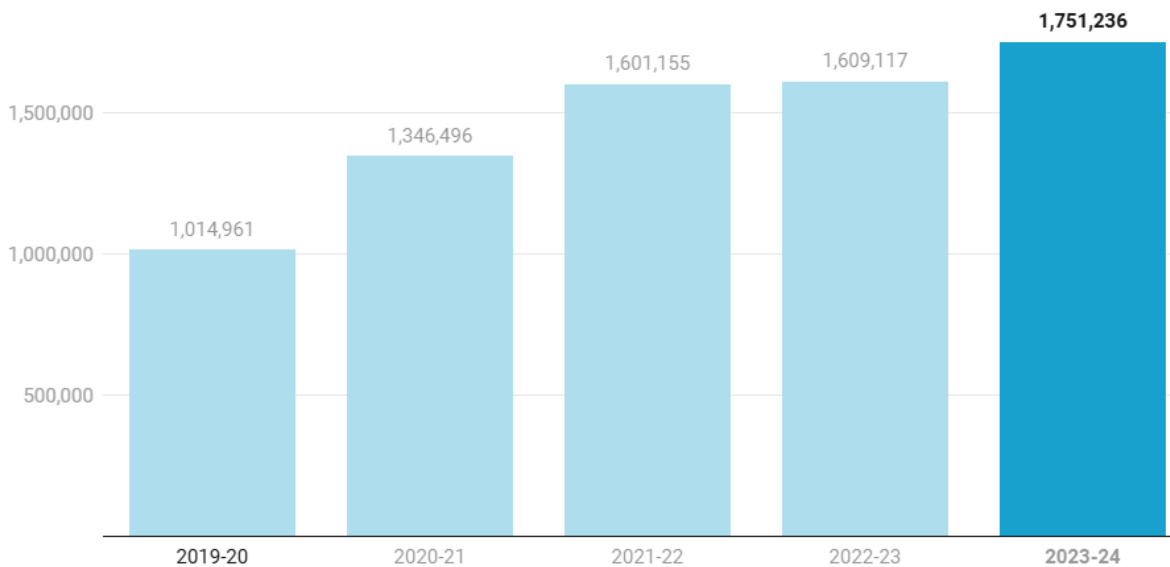
- अनौपचारिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण: ज्वलन और एसडि लीचिंग जैसी संकटजनक विधियों का उपयोग करके अनौपचारिक ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण से वशिकृत धुआँ उत्सर्जित होता है तथा मृदा एवं जल दूषित हो जाता है, जिससे पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न होता है।
  - चीन, भारत, पाकिस्तान, वियतनाम और फिलीपींस के अनौपचारिक रीसाइकलिंग बाजार विश्व के 50% से 80% ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करते हैं।
- बुनियादी ढाँचे का अभाव: ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिये बुनियादी ढाँचे, जिसमें अपर्याप्त संग्रहण बंदि और पुनर्चक्रण सुविधाएँ शामिल हैं, से अनुचित निपटान की समस्या उत्पन्न होती है।
  - इसके परिणामस्वरूप ई-अपशिष्ट लैंडफिल में पहुँचता है, जिससे संकटजनक रसायनों से मृदा और जल संदूषित हो जाता है।
- जागरूकता का अभाव: उचित निपटान और पुनर्चक्रण के संबंध में उपभोक्ताओं, व्यवसायों तथा नीति निर्माताओं में जागरूकता का अभाव है।
  - उदाहरण के लिये, व्यक्ति अपने ई-अपशिष्ट को नियमित कूड़ेदानों में फेंक सकते हैं या उसे ऐसे दान-संस्थाओं को दान कर सकते हैं जिनके पास ई-अपशिष्ट का उचित रूप से प्रबंधन करने हेतु उचित संसाधन का अभाव है।
- ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव: ई-अपशिष्ट से पर्यावरण को नुकसान होता है क्योंकि वशिकृत पदार्थ (जैसे- सीसा, कैडमियम और पारा) जल, मृदा

तथा वायु को दूषित करते हैं, जिससे वन्य जीवन प्रभावित होता है।

- अनुचित निपटान से [भूजल प्रदूषण](#), [वायु प्रदूषण](#) और [मृदा क्षरण](#) बढ़ता है।

## India's e-waste surges by around 73 per cent in five years

E-Waste Generation(Metric Ton)



## कनि कार्यनीतियों से भारत में ई-अपशष्ट के प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है?

- **अनौपचारिक क्षेत्र का एकीकरण:** संग्रहण दरों को बढ़ाने के लिये अनौपचारिक अपशष्ट संचालकों को औपचारिक प्रणालियों में एकीकृत किया जाना चाहिये। सुरक्षित हैंडलिंग तकनीकों पर अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्त्ताओं के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना आवश्यक है।
  - उदाहरण के लिये, चीन अपशष्ट वदियुत और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (WEEE) की पुनर्प्राप्ति तथा निपटान के प्रबंधन पर वनियमन के माध्यम से प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के साथ अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाता है।
- **तकनीकी प्रगत:** दक्षता बढ़ाने के लिये उन्नत रीसाइकलिंग प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और बेहतर ई-अपशष्ट ट्रैकिंग तथा संग्रहण प्रणालियों के लिये AI एवं [IoT-आधारित समाधान](#) वकिसति करने की आवश्यकता है।
  - यूरोपीय संघ के "मरम्मत के अधिकार" नियम के अंतर्गत निर्माताओं के लिये वस्तुओं की मरम्मत के दायित्वों को स्पष्ट किया गया है तथा उपभोक्ताओं को मरम्मत के माध्यम से उत्पाद के जीवनचक्र को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- **वैश्विक प्रथाओं से सीख लेना:**
  - **यूरोपीय संघ:** कठोर पुनर्चक्रण लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहिये तथा उत्पादकों के लिये पारसिथितिकी-डज़ाइन प्रोत्साहन बढ़ाया जाना चाहिये।
    - उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ (EU) द्वारा [अपशष्ट वदियुत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण \(WEEE\)](#) नरिदेश।
  - **जापान:** रीसाइकलिंग पहलों को प्रभावी ढंग से वतितपोषित करने और समर्थन देने के लिये राष्ट्रव्यापी ई-अपशष्ट रीसाइकलिंग शुल्क करयिन्वति किये जाने की आवश्यकता है।
    - जापान घरेलू उपकरण पुनर्चक्रण वधि(HARL) के माध्यम से [वसितारित उत्पादक उत्तरदायित्व \(EPR\)](#) पर ज़ोर देता है।
- **नवीनीकरण और पुनः उपयोग कार्यक्रम:** कंपनियों को पुनर्विक्रय के लिये प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का नवीनीकरण करने के लिये प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिये, जिससे उनके जीवन चक्र का संवर्द्धन किया जा सके।
  - उदाहरण: जर्मनी में उपभोक्ताओं को पुराने उपकरणों की मरम्मत या नवीनीकरण के लिये नरिदिष्ट केंद्रों पर इसे वापस किये जाने की सुविधा उपलब्ध है।
  - ई-अपशष्ट को कम करते हुए वहीनीय इलेक्ट्रॉनिक्स को सुलभ बनाने के लिये संगठित सेकंड-हैंड बाज़ारों का सुदृढीकरण किया जाना चाहिये।
- **जन जागरूकता और शक्ति:** ई-अपशष्ट के खतरों और उचित निपटान वधियों पर शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के नवासियों के लिये जन जागरूक अभियान आयोजित करना चाहिये।
  - जन संपर्क कार्यक्रमों के लिये गैर सरकारी संगठनों और थकि टैकों के साथ सहयोग किया जा सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय नकियों के साथ सहयोग:** रीसाइकलिंग प्रौद्योगिकियों में क्षमता निर्माण के लिये [अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ \(ITU\)](#) जैसे संगठनों के साथ साझेदारी की जानी चाहिये।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न:**

प्रश्न. पुराने और प्रयुक्त कंप्यूटरों या उनके पुर्जों के असंगत/अव्यवस्थित निपटान के कारण, निम्नलिखित में से कौन-से ई-अपशिष्ट के रूप में पर्यावरण में नरिमुक्त होते हैं? (2013)

1. बोरलियम
2. कैडमियम
3. क्रोमियम
4. हेप्टाक्लोर
5. पारा
6. सीसा
7. प्लूटोनियम

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
- (b) केवल 1, 2, 3, 5 और 6
- (c) केवल 2, 4, 5 और 7
- (d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

उत्तर: (b)

**प्रश्न:**

प्रश्न. नरितर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस अपशिष्ट की वशाल मात्राओं का नसितारण करने में क्या-क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परविश में जमा होते जा रहे वषिले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से कसि प्रकार हटा सकते हैं? (2018)